



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



# TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(17 September 2023)

## Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

## Important News:

- ग्लोबल साउथ: वैश्विक शासन में बदलाव की बयार
- Google पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा
- 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) का प्रेरक क्या रहा है?
- टीबी रोगियों के लिए 'व्यापक पोषण' संबंधी सहायता

## ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



## ग्लोबल साउथ: वैश्विक शासन में बदलाव की बयार

### संदर्भ:

- ग्लोबल साउथ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जो समकालीन वैश्विक राजनीति के विश्लेषण में एक प्रमुख मेटा-श्रेणी के रूप में उभर रहा है।



- ग्लोबल साउथ वैश्विक क्षेत्र में इसकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। वैश्विक व्यवस्था से यह जुड़ाव 'ग्लोबल साउथ' के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, विविध संस्कृतियों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपनी विशाल जनशक्ति के कारण दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## हाल ही में, ग्लोबल साउथ की भूमिका विश्व भू-राजनीति और विकास में कैसे महत्वपूर्ण हो रही है?

- हाल के वैश्विक सम्मेलनों, शिखर सम्मेलनों और विश्व नेताओं की सभाओं में ग्लोबल साउथ की उपस्थिति और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, इस अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने इस गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। मेजबान राष्ट्र और अध्यक्ष के रूप में, दक्षिण अफ्रीका ने अपने मिशन को "वैश्विक दक्षिण के एजेंडे को आगे बढ़ाने" के रूप में व्यक्त किया।
- इसी तरह, इस मई में हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर, जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में ग्लोबल साउथ के महत्व को रेखांकित किया, इस बात पर जोर दिया कि आमंत्रित अतिथि देश इस बढ़ते महत्व का सही प्रतिनिधित्व करते हैं।
- रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में शुरू हुए मौजूदा संकट ने अचानक ग्लोबल साउथ को अंतरराष्ट्रीय बहस और चर्चा में ला दिया है।
- भारत में नवीनतम जी20 शिखर सम्मेलन ने एक बार फिर ग्लोबल साउथ की आवाज को जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित किया है। भारत की अध्यक्षता में 55 सदस्यीय अफ्रीकी संघ (एयू) को जी20 में शामिल करने के साथ, जी20 ने इस अंतरसरकारी मंच में ग्लोबल साउथ की प्रधानता स्थापित की है।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## ग्लोबल साउथ ग्रुपिंग क्या है?

- भले ही यह कैसा लगता है, यह वास्तव में एक भौगोलिक शब्द नहीं है। ग्लोबल साउथ में शामिल कई देश उत्तरी गोलार्ध में हैं, जैसे भारत, चीन और अफ्रीका के उत्तरी आधे हिस्से में स्थित सभी देश। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों दक्षिणी गोलार्ध में हैं, ग्लोबल साउथ में नहीं हैं।
- अधिकांश लोग तथाकथित ब्रांट रेखा को सीमा के रूप में उद्धृत करते हैं।
- नई दिल्ली स्थित काउंसिल फॉर स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च के संस्थापक हैप्पीमोन जैकब कहते हैं कि *"ग्लोबल साउथ एक भौगोलिक, भू-राजनीतिक, ऐतिहासिक और विकासात्मक अवधारणा है, सभी एक ही समय में - अपवादों के साथ"*।

## कौन से देश ग्लोबल साउथ बनाते हैं?

- "ग्लोबल साउथ" शब्द उन देशों को संदर्भित करता है जो विकासशील, कम विकसित और अविकसित की श्रेणी में आते हैं।
- इनमें से अधिकांश देश दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीपों से आते हैं, लेकिन सभी नहीं।
- "ग्लोबल साउथ" शब्द का पहली बार उल्लेख वर्ष 1969 में कार्ल ओग्लेस्वी नामक एक राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा किया गया था।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- वास्तव में, उन्होंने स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी (SDS) नामक एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सार्वजनिक रूप से वियतनाम युद्ध का विरोध किया। कॉमनवील नामक वैश्विक कैथोलिक पत्रिका में लिखते समय, उन्होंने दृढ़ता से वकालत की कि वियतनाम में युद्ध ग्लोबल साउथ पर उत्तरी प्रभुत्व के इतिहास का परिणाम था।

- **77 देशों का समूह (G-77):**

- 1964 तक, विकासशील विश्व पहले से ही संगठित होना शुरू हो गया था। 1964 में, 77 देशों का समूह (G-77) जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के पहले सत्र में एक 'संयुक्त घोषणा' पर हस्ताक्षरकर्ता बन गया, जो विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतरसरकारी संगठन बन गया।
- आज, जी-77, जिसने एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया (या एशिया-प्रशांत) के देशों में कई विस्तारों के बावजूद अपना नाम बरकरार रखा है, में 134 देश शामिल हैं।
- चूंकि चीन तकनीकी रूप से इस समूह से संबंधित नहीं है, इसलिए अधिकांश बहुपक्षीय मंचों पर इसे 'जी-77+चीन' कहा जाता है।

**ADDRESS:**



## ग्लोबल साउथ क्यों महत्वपूर्ण है?

- ग्लोबल साउथ मायने रखता है क्योंकि इन देशों ने वर्तमान समय में दुनिया के आधे विकास में सीधे योगदान दिया है। वे सभी दुनिया की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के घर हैं और दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।
- एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रवासी श्रमिकों से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को आने वाला धन पिछले साल 466 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह इन देशों में कई मिलियन परिवारों को गरीबी और भुखमरी से बचाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।
- इसके अलावा उनके बीच अंतर-व्यापार हाल के वर्षों में पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि यह वैश्विक व्यापार के एक चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- ग्लोबल साउथ के अविकसित होने का श्रेय अतीत में ग्लोबल नॉर्थ के देशों द्वारा इन देशों के उपनिवेशीकरण को दिया जा सकता है।
- अंततः, जलवायु संकट को रोकने में आज बच्चों और युवाओं द्वारा साझा की गई भूमिका और जिम्मेदारियां उल्लेखनीय हैं। वे पूरी तरह से फैल रहे हैं और लोगों को

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



उनकी समृद्ध जैव विविधता और निकट भविष्य में इसे संरक्षित करने के तरीकों और साधनों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। संपूर्ण वैश्विक दक्षिण देश एक साथ नवाचार, सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता का एक समृद्ध मोज़ेक हैं।

## क्या भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकता है?

- हाल के जी20 शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व ने निस्संदेह देश को वैश्विक दक्षिण की आवाज बना दिया है। यह निश्चित रूप से समूह का नेतृत्व कर सकता है लेकिन केवल ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे अन्य बड़े लीग देशों के करीबी समन्वय के साथ।
- वर्तमान में ग्लोबल साउथ बड़े पैमाने पर एक मजबूत दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) की मांग करता है। आज SSC के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग विकासशील देशों में SDG को आगे बढ़ाने में सहायक है।
- अंततः, ग्लोबल साउथ आगे बढ़ता रहेगा है। यह ग्लोबल नॉर्थ के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसका घटता प्रभाव हर जगह महसूस किया जा रहा है।
- निश्चित रूप से, "बचे हुए के उदय (Rise of the Rest)" का समय आ गया है और वैश्विक उदारवादी व्यवस्था के नेताओं को उभरते और चमकते वैश्विक दक्षिण के साथ मिलकर काम करना होगा।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



## Google पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा:

### मामला क्या है?

- 12 सितंबर को, अमेरिकी सरकार ने यह पता लगाने के लिए 10-सप्ताह का मुकदमा शुरू किया कि क्या तकनीकी दिग्गज Google प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए खोज इंजन बाजार में अपने प्रभुत्व का अवैध रूप से दुरुपयोग कर रहा है।



- कुछ पर्यवेक्षकों के लिए, वाशिंगटन डीसी अदालत में शुरू हुई सुनवाई को "आधुनिक इंटरनेट युग में तकनीकी शक्ति पर सबसे परिणामी मुकदमा" के रूप में देखा जा रहा है।

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## गूगल पर आरोप क्या है?

- वर्तमान मामले में, 37 राज्यों के गठबंधन के साथ अमेरिकी न्याय विभाग का तर्क है कि स्मार्टफोन और वेब ब्राउज़र पर डिफ़ॉल्ट खोज प्रदाता के रूप में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए, Apple और मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स सहित अन्य को Google सालाना 10 बिलियन डॉलर का भुगतान करके अवैध रूप से प्रतिस्पर्धा को दबा रहा है।
- मूल रूप से 2020 में एक संघीय अदालत में दायर, सरकार के मुकदमे में कहा गया है कि इन सौदों का उद्देश्य "बहिष्करण" था क्योंकि उन्होंने Google के प्रतिद्वंद्वियों को खोज क्वेरी और क्लिक तक पहुंच से वंचित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप Google को अपना एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति मिली।
- यह कहते हुए कि Google संयुक्त राज्य अमेरिका में खोज इंजनों के बीच 90 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रखता है, मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि इन "ब्राउज़र समझौतों" के परिणामस्वरूप हर दिन Google की ओर अरबों प्रश्न आते हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प होते हैं।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## Google ने इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

- इस बात से इनकार करते हुए कि उसने अपने प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए इन समझौतों का अवैध रूप से उपयोग किया था, Google ने कहा कि उसने केवल एक बेहतर उत्पाद प्रदान किया था।
- Google का तर्क है कि वैश्विक खोज बाजार के 90 प्रतिशत हिस्से पर उसके नियंत्रण का कारण यह है कि वह प्रतिस्पर्धा की कमी के बजाय बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करता है।
- Google का कहना है कि उपभोक्ता हमेशा डिफॉल्ट विकल्प को बदलना चुन सकते हैं, और एप्पल जैसे डिवाइस निर्माताओं के साथ इसका कोई भी सौदा कानून के ऊपर है।

## क्या Apple और Google के बीच कोई डील हुई है?

- जबकि Apple और Google दोनों अपने सहयोग के बारे में गुप्त रहे हैं, कई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इस तरह का सौदा 2017 में नवीनीकरण किया गया था।
- द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, जबकि Google ने 2014 में Apple को 1 बिलियन डॉलर का भुगतान किया था, अब 8 बिलियन डॉलर से 12 बिलियन डॉलर, तक मिलते हैं जो एप्पल के वार्षिक सकल लाभ का 9% है।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- हालांकि Google की इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने की इच्छा इस तथ्य से भी प्रेरित है कि उसका 75% खोज राजस्व iPhone और iPad उपयोगकर्ताओं से आता है। यह एक एहतियाती कदम भी है क्योंकि यह Apple द्वारा एक प्रतिद्वंद्वी खोज इंजन के निर्माण को रोकता है, जो उन कुछ कंपनियों में से एक है जिनके पास Google को टक्कर देने का साधन है।
- Google व्यावहारिक अर्थशास्त्र से एक महत्वपूर्ण सबक भी समझता है - अधिकांश लोग उन्हें उपलब्ध कराए गए डिफ़ॉल्ट विकल्पों को बदलने की जहमत नहीं उठाएंगे।

### 'एंटीट्रस्ट' के मुद्दों पर 'टेकलैश' क्यों है?

- Google एंटीट्रस्ट मामलों के लिए कोई अजनबी नहीं है, हालांकि अमेरिका में नहीं। 2017 में, खोज परिणामों में अपनी सेवाओं के लिए अनुचित प्राथमिकता दिखाने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा उस पर 2.7 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। यूरोपीय संघ ने तीन एंटी-ट्रस्ट जांचों पर Google पर कुल 8.25 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है।
- दूसरी ओर, अमेरिका घरेलू दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई करने में धीमा रहा है, जो राजनीतिक पैरवी पर काफी मात्रा में धन और प्रयास भी खर्च करते हैं।



- Google के खिलाफ मौजूदा मामले में यह फिर से परिभाषित करने की क्षमता है कि प्रौद्योगिकी युग में नए बिजनेस मॉडल के खिलाफ एंटी-ट्रस्ट कानून कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि एंटी-ट्रस्ट कानून के तहत उपभोक्ता हानि का एक प्रमुख परीक्षण कंपनियों के एकाधिकारवादी व्यवहार के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली मौद्रिक हानि की मात्रा है।

## भारत में क्या हुआ था?

- भारत की प्रतिस्पर्धा नियामक संस्था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI ) ने पिछले साल Google को एंड्रॉइड इकोसिस्टम में अपने प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण को बदलने का आदेश दिया था और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए Google पर 1,338 करोड़ रुपये या 161.95 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। इसके बाद, Google ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष अपील दायर की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- मार्च में, NCLAT ने अविश्वास उल्लंघन के लिए Google पर CCI के 130+ करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा, जबकि पिछले अक्टूबर के अपने निष्कर्षों की काफी हद तक पुष्टि करते हुए कहा कि Google ने एंड्रॉयड पारिस्थितिकी तंत्र में अपने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग किया। इसने माना कि इसके संपूर्ण Google मोबाइल सुइट की प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य है। यह "ओईएम" या मूल उपकरण निर्माताओं पर अनुचित शर्तें थोपना है, जो कंपनी द्वारा "प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग" है।
- आखिरकार, Google ने NCLAT के आदेश के खिलाफ जून में शीर्ष अदालत का रुख किया। हालांकि, इस मामले पर अभी भी फैसला होना बाकी है।

**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080  
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com  
info@vajiraoinstitute.com



## 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) का प्रेरक क्या रहा है?

### संदर्भ:

- 10 सितंबर को, नई दिल्ली में वार्षिक जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर, भारत के नेतृत्व वाला ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA) नामक समूह अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है।



- यह समूह जैव ईंधन के क्षेत्र, विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र, में सह-विकास करने, उत्पादन प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति में तेजी लाने और इसके उपयोग की वकालत करने के लिए देशों को एक साथ लाने का प्रयास करेगा।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- तीन संस्थापक सदस्यों, भारत, अमेरिका और ब्राजील के साथ अर्जेंटीना, कनाडा, इटली और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुए, जो जी-20 सदस्य देश भी हैं।

## जैव ईंधन क्या होते हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) जैव ईंधन की परिभाषा *"बायोमास से प्राप्त तरल ईंधन के रूप में जिसका उपयोग पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन जैसे जीवाश्म ईंधन आधारित तरल परिवहन ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है"* के रूप में करती है।

## क्या जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का विकल्प बन सकते हैं?

- ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ जैव ईंधन और टिकाऊ जैव ईंधन के बीच अंतर करते हैं। जैव ईंधन गन्ना, मक्का या सोयाबीन जैसी फसलों से प्राप्त होता है, और टिकाऊ जैव ईंधन कृषि अपशिष्ट, खाना पकाने के तेल और वसा जैसे संसाधित पशु अवशेषों से प्राप्त होता है।
- पहले को बोलचाल की भाषा में 1G इथेनॉल, या पहली पीढ़ी का जैव ईंधन कहा जाता है, और बाद वाले को 2G, यानी दूसरी पीढ़ी कहा जाता है।
- यह अंतर अब तेजी से फोकस में आ गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है, खेती के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता के कारण खाद्य सुरक्षा के खतरे

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



और जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान की आशंका है। अनुमान बताते हैं कि आज आधी से अधिक उत्पादक भूमि पर खेती की जाती है, और कृषि दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में से एक है।

- GBA ने इस बात पर जोर दिया है कि उसका ध्यान 2जी इथेनॉल विकसित करने पर होगा।

### जैव ईंधन पर नए सिरे से ध्यान क्यों दिया जा रहा है?

- यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में गंभीर व्यवधान के साथ, कई देश पेट्रोल और डीजल पर आयात निर्भरता के विकल्प खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारत अपने कच्चे तेल का 87% आयात करता है, और यह देश के लिए मुख्य आरक्षित मुद्रा व्यय है।
- वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का लगभग एक-चौथाई हिस्सा परिवहन के कारण होता है, इस क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए गए हैं, कई देशों ने बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीतियों की घोषणा की है और पुराने वाहन निर्माता अब EV क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन विमानन, शिपिंग और लंबी दूरी की ट्रकिंग जैसे परिवहन के कुछ तरीकों के लिए स्व-चालित कारों या मोटरबाइकों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को कम करना कठिन होगा।

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- यहीं पर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2जी इथेनॉल एक मूल्यवान विकल्प हो सकता है।

## क्या जैव ईंधन ऊर्जा परिवर्तन या संक्रमण में सहायता करते हैं?

- आज अधिकांश जैव ईंधन को अलग-अलग स्तर पर पेट्रोल या डीजल के साथ मिश्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत लगभग 10% जैव ईंधन का मिश्रण करता है और आने वाले वर्षों में इसे दोगुना करने की योजना है।
- जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि EV को अपनाने में तेजी लाना और हरित हाइड्रोजन जैसे विकल्प विकसित करना, चल रहे ऊर्जा परिवर्तन का ध्यान होना चाहिए।
- वहीं दूसरों का तर्क है कि 2जी इथेनॉल परिवहन क्षेत्र में आसन्न व्यवधान या चुनौतियों को कम करेगा। यह आंतरिक दहन इंजनों के जीवन को बढ़ाते हुए ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने की अनुमति देकर, वाहन निर्माताओं को मजबूत विकल्प विकसित करने के लिए समय देकर, किसानों की आय में वृद्धि और नौकरियां प्रदान करके ऐसा करेगा।

## आगे क्या होने वाला है?

- GBA के तीन संस्थापक सदस्य, भारत, अमेरिका और ब्राजील, 85% वैश्विक जैव ईंधन का उत्पादन करते हैं और इसका लगभग 81% उपभोग करते हैं।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- जैव ईंधन के उपयोग और उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास के अनुरूप, अमेरिका ने जैव ईंधन के उत्पादन में काफी वृद्धि करने और 2025 तक कच्चे तेल के आयात के प्रतिदिन लगभग 1,40,000 बैरल का विकल्प देने के लिए अपने नवीनतम संशोधित "नवीकरणीय ईंधन मानक" की घोषणा की।
- इसी तरह, भारत ने 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण को पूरा करने के लक्ष्य के साथ 2018 की शुरुआत में 12 नई रिफाइनरियों की स्थापना की घोषणा की थी। भारत की 2070 तक नेट जीरो (वातावरण से उतना कार्बन हटाना जितना मानव गतिविधि उत्सर्जित करती है) बनने की घोषणा के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
- IEA का अनुमान है कि वैश्विक जैव ईंधन मांग का लगभग दो-तिहाई हिस्सा तीन उभरती अर्थव्यवस्थाओं - भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया से आएगा, और उनके पास *"पर्याप्त घरेलू फीडस्टॉक, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत और नीतियों का एक पैकेज जिसका वे मांग बढ़ाने के लिए लाभ उठा सकते हैं"* भी है।
- हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह वास्तव में ऊर्जा क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाएगा।

साभार: The Hindu

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## टीबी रोगियों के लिए 'व्यापक पोषण' संबंधी सहायता:

### मामला क्या है?

- कुपोषण एवं अल्पपोषण टीबी रोग का प्रमुख जोखिम कारक है। 2019 में, स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव प्रीति सूदन ने कहा था कि जनसंख्या में व्याप्त व्यापक स्तर पर कुपोषण भारत में वार्षिक टीबी की घटनाओं में 55% का योगदान देता है।

### टीबी रोगियों के लिए व्यापक पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता:

- 2022 के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 45% लोग अल्पपोषित हैं, जिससे हर साल लगभग 12 लाख टीबी के मामले सामने आते हैं।



- इसके बावजूद भी, अप्रैल 2018 में आकर ही 'पोषण सहायता' राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम का हिस्सा बन पायी, जब 'निक्षय पोषण योजना' - टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना - शुरू की गई।

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- इस कार्यक्रम के तहत, टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खाते में इलाज की अवधि के दौरान प्रति माह ₹500 जमा किए जाते हैं।
- सितंबर 2022 में, भारत ने सहमति प्राप्त टीबी रोगियों के लिए 'नि-क्षय मित्र' नामक एक और पोषण सहायता कार्यक्रम शुरू किया।
- उल्लेखनीय है कि ये सभी पहल केवल टीबी रोगियों को मृत्यु दर कम करने के लिए पोषण सहायता प्रदान करती हैं, न कि परिवार के सदस्यों को टीबी रोग को रोकने के लिए। जबकि निदान के समय टीबी रोगियों की पोषण स्थिति काफी हद तक परिवार के पोषण स्तर का प्रतिबिंब है।
- भारत में टीबी के रोगियों के लिए पोषण संबंधी देखभाल और सहायता पर 2017 के मार्गदर्शन दस्तावेज़ में सिफारिश की गई थी कि परिवार के सदस्यों को एक "भोजन की टोकरी, क्योंकि उनमें खाद्य असुरक्षा, लंबे समय से ऊर्जा की कमी और टीबी होने का उच्च जोखिम होने की संभावना है" प्रदान किया जाए। यह अभी वास्तविकता बनना बाकी है।
- झारखंड की RATIONS योजना: इस योजना में टीबी रोग की रोकथाम के लिए परिवार के सदस्यों को पोषण सहायता प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया है। परीक्षण में, पोषण संबंधी सहायता के माध्यम से 39% (टीबी के सभी प्रकार) से 48% (फुफ्फुसीय टीबी) में घरेलू संपर्कों के बीच टीबी रोग को रोका गया।

**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## 'नि-क्षय पोषण' योजना से जुडी चुनौतियां:

- भारत टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 24 लाख अधिसूचित टीबी मामलों में से केवल 16 लाख (66%) को नि-क्षय पोषण योजना कार्यक्रम के तहत 2022 में कम से कम एक महीने का भुगतान प्राप्त हुआ।
- पिछले तीन वर्षों में लाभार्थियों की संख्या में बहुत कम वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, 2021 में, भारत में 21 लाख अधिसूचित मामलों में से केवल 62.1% को कम से कम एक भुगतान प्राप्त हुआ। 2020 में भी, केवल 62% अधिसूचित टीबी मामलों को कम से कम एक महीने का भुगतान मिला।
- जनवरी 2022 में, जनवरी-सितंबर 2019 के दौरान 426 रोगियों के बीच किए गए, पूर्वव्यापी समूह अध्ययन में पाया गया कि बुनियादी दस्तावेजों की कमी के कारण सहायता उन गरीबों तक नहीं पहुंच रही है, जिन्हें पोषण संबंधी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस अध्ययन में पहली किस्त प्राप्त करने में 56 दिनों की देरी भी दर्ज की गई। साथ ही, 49% मरीजों को इलाज पूरा होने के बाद आखिरी किस्त मिली।
- टीबी रोगियों का मानना था कि नि-क्षय पोषण योजना कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता "उपचार के दौरान पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए अपर्याप्त" थी।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)